Shri Tan Singh:
Shri Maurya:
Shri P. L. Barupal:
Shri P. H. Bheel:
Shri Himmatsinhji:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Nath Pai:
Shri Bagri:
Shri Daljit Singh:
Shri Sadhu Ram:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees Welfare Association (Regd.), New Delhi submitted a memorandum to him on the 3rd March, 1966 on the subject of reservation of posts in Government services for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) Yes, Sir.

(b) Government of India have not found it possible to accept any of the demands made in the above memorandum.

Telegraphic Communications to and from Tripura

*1628. **Shri H. N. Mukerjee:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the telegraphic communication to and from Tripura has been of late subject to much dislocation; and

(b) whether it is also a fact that such breakdown is due to the diversion elsewhere of transmission machinery intended for Agartala, Tripura?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) No.

(b) Does not arise.

दिल्ली में टेलीफोन सेवा

*1629. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में टेलीफोन सेवा के अस्त-व्यस्त हो जाने के संबंध में कुछ समय पूर्व उन्हें कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था अथवा प्रतिनिधि मण्डल मिला था ;

(ख) क्या टेलीफोन बिलों के संबंध में तथा टेलीफोन कनेक्शनों के काट दिये जाने पर होने वाली कठिनाईयों के अतिरिक्त उक्त प्रतिनिधि मण्डल ने कुछ अन्य कठिनाईयों की ओर उनका ध्यान दिलाया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग) हाल में ही नागरिक परिषद् के प्रतिनिधि-मण्डल ने एक अभ्यावेदन दिया था। यह अभ्यावेदन मुख्यत : बिलों की अदायगी न करने के कारण टेलीफोन काट देने से संबंधित है। इस प्रतिनिधिमण्डल ने टेलीफोन सेवा के संबंध में भी प्रासंगिक तौर पर जिक्र किया।

सन्तोषपूर्ण सेवा जुटाने के लिए सदैव संशोधनात्मक तथा रिक्षात्मक तरीके अपनाये जाते हैं। किसी भी स्थिति में दिल्ली में टेलीफोन सेवा के कार्य संचालन में किसी प्रकार की तथाकथित गिरावट का संकेत नहीं मिलता।

हिन्दी सम्बन्धी नीति

1630. **श्री विश्वनाथ प्रसाद :**
श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय :

श्री प्रिय गुप्त :
श्री राजदेव सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिन्दी कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दी पत्रों के उत्तर या तो अंग्रेजी में दिये जाते हैं अथवा उनमें विलम्ब किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि इसके लिये कोई ठीक कारण बताना सम्भव नहीं है किन्हीं सरकारी कर्मचारियों में इस गलत धारणा की सम्भावना को नहीं रोका जा सकता, कि गत वर्ष के प्रारम्भ में हुई घटनाओं के बाद केन्द्र की राजभाषा हिन्दी होने के संबंध में सरकार की नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन होगा।

(ग) जी, नहीं। हिन्दी के पत्रों के उत्तर सामान्यतः हिन्दी में ही भेजे जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

Motor Boat Workers.

5122. Shri A. K. Gopalan: Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the motor boat workers at Baliapatam, Cannanore District are not getting the minimum wages fixed;

(b) if so, whether Government propose to take action against those responsible;

(c) whether it is a fact that the increase in line *bhatta* and bonus are some of the demands put forward by the workers;

(d) the action taken by the Labour Department and the result thereof; and

(e) whether Government propose to take immediate steps to implement the minimum wages to those workers?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) The Motor Boat Workers' Union, Baliapatam raised a dispute regarding non-payment of minimum wages and bonus for the year 1964 and increase in line *bhatta* etc. with the managements concerned. The District Labour Officer, Cannanore intervened and the dispute was settled in a conference held on 26th November, 1965. As per the terms of agreement the managements agreed to pay a flat rate increase of Rs. 7.50 per month to all workers over the then existing rates.

(b) The Union representatives were advised to file claim petitions regarding the non-payment of minimum wages.

(c) Yes.

(d) The Labour Department of the Kerala Government initiated conciliation proceedings. The dispute regarding bonus was settled. The demand for increase in line *bhatta* was not pressed by the Union.

(e) The workers and the Union representatives have been advised to file claim petitions in the Labour Court for minimum wages so as to facilitate appropriate action being taken.